

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-354
उत्तर देने की तारीख-22/07/2026

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संकाय पदों की रिक्तियां

354 #श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में संकाय सदस्यों के स्वीकृत पदों और वर्तमान रिक्तियों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रमुख संस्थानों में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के बैकलॉग पदों को भरने के लिए चलाए गए विशेष भर्ती अभियानों के अंतर्गत अब तक कितनी नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) संकाय सदस्यों की कमी के कारण उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सहित शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई) संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती शक्तियां संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं।

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की वजह से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से पुनः से मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सीयू, आईआईटी और एनआईटी सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 32114 पदों को भरा गया है। उक्त अवधि के दौरान इन 32114 पदों में से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने सामूहिक रूप से 28823 पदों (एससी-3487, एसटी-1523, अन्य पिछड़ा वर्ग-6095, ईडब्ल्यूएस-1108) को भरा है, जिसमें 17062 संकाय पद (एससी-2087, एसटी-854, ओबीसी-3631, ईडब्ल्यूएस-527) शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण संकाय को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रित करना आदि शामिल हैं। सीएचईआई द्वारा बहु-चरणीय और मजबूत स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके संकाय भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभिन्न संस्थानों के अधिनियम और कानून, चयन समितियों की संरचना, विभिन्न स्तरों संकाय की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और विजिटर के द्वारा मनोनित आदि के प्रावधान को स्पष्ट करते हैं ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक सामान्य पोर्टल 'सीयू-चयन' शुरू किया है, जिसमें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इन सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत ने अपनी वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) रैंकिंग में वर्ष 2013 में 66वें स्थान से आगे बढ़कर वर्ष 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। डब्ल्यूआईपीओ के विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के अनुसार भारत पेटेंट आवेदनों की संख्या के मामले में 8वें स्थान (2012 में) से छठे स्थान (2022 में) पर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'अनुसंधान और विकास सांख्यिकी एक नजर में 2022-23' के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग (एस एंड ई) में प्रदान की गई पीएचडी डिग्रियों की संख्या के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) डेटाबेस के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रकाशनों की कुल संख्या के मामले में भारत 2022 में (2012 में 6वें स्थान से) तीसरे स्थान पर रहा।
